

## श्रम विभाग

## आदेश

दिनांक नवम्बर, 1985

सं० ओ० वि०/45359.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भिवानी, टैक्सटाईल मिल, भिवानी, के श्रमिक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है, अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं/हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

- (1) Whether the members did not strike work w.e.f. 24th August, 1985 to 25th September, 1985 ? If so, to what relief they are entitled to ?
- (2) Whether the workers of Process House, Weaving Preparatory, Finish Folding, Weaving and Gray Folding are entitled to any compensation for no work w.e.f. 28th August, 1985 to 25th September, 1985 due to alleged strike by the members ? If so, with what details ?

कुलवन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 6 नवम्बर, 1985

सं० ओ० वि०/सोनीपत/163-85/44853.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दशमेश एग्रो इण्डस्ट्रीज, एम 17, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, सोनीपत के श्रमिक श्री प्रेम पाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम पाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/सोनीपत/164-85/44860.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कुन्दरा शूज़ प्रा० लि०, कण्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री सदा वृक्ष तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सदा वृक्ष की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

जे. पी. रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम विभाग।